



## हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की ईवीएम होंगी चेक दोनों बीजेपी ने जीती

कांग्रेस उम्मीदवारों की वोटिंग में गढ़बड़ी की शिकायत

पार ईसीआई का फैसला

चंगीगढ़ (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गढ़बड़ी की शिकायत की जाओ जो के आदेश दिए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद सीट



शामिल है। जिनकी अब ईवीएम घोक कराई जाएगी। करनाल से केंद्रीय भारी मोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तो चुनाव जीते थे। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गढ़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी थी थी। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जाच करने की मांग की थी।

## करमीर से खदेड़े गए आतंकी तो जम्मू को बनाया नया ठिकाना

● खात्मे का ऐवंशन प्लान भी तैयार, सुरक्षा एजेंसियों ने कसी कमाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू को निशाना बनाने की कांग्रेस आतंकियों ने अनुच्छेद 370 खास होने के करीब दो साल के भीतर ही 2021 में शुरू कर दी थी। ये टीम घाटी में आतंकियों पर सख्ती हो रही थी तो उनके गुट जम्मू में पैठ बनाने के लिए गुप्तपुर मुहिम चला



रह रहे। ताजा हमलों की जानकारी में पता चला है कि आतंकियों ने जम्मू के कई इलाकों में अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। उन्होंने ओवर ग्राउंड कर्कर की अच्छी खासी टीम खड़ी कर ली है। ये टीमें उनकी सहायता के अलावा उनके लिए मुख्यिरी भी कर रही हैं।

## सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अवलत ने मनी लालिंगा से जुड़े केस में उन्हें जमानत दी है। कोर्ट ने एक लाख मुचुकाने पर जमानत दी है।

इस आधार पर जमानत का ईडी ने किया था विरोध

केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी सघ किया कि रिक्षत के आयोग केंद्रीय जांच ब्लॉ



(सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आय पार्टी के लिए साउथ रूप से रिक्षत की मांग की। अगर आम आदी पार्टी (आप) को मामले में आयोगी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी घराया जाएगा।

ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मीष सिसोदिया को आयोगी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदी पार्टी के आयोगी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

## संसद में मूर्तियों की जगह बदलने पर राजनीति तेज

● खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और पराषटपति को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद परिसर में जगह-जगह स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराषटपति पर लिखकर इसका विरोध जताया है। सरकार ने अपने इस फैसले में संसद परिसर में जगह-जगह लगी मूर्तियों को परिसर में ही एक नए स्थान प्रेरणा करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन्मतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ावा में जन्मतम समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति विंटर कर दिया गया है। मोहरी सरकार-3.0 की दूसरी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति विंटर कर दिया गया है। मोहरी सरकार-3.0 की दूसरी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धन, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कापास सहित 14 खरीफ फैसलों के नए न्यूनतम

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र की नरेंद्र मोहरी सरकार ने तीसरा कार्यकाल संभालते ही दो दिनों के अंदर देशभर के किसानों को डबल तोहफा दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून-जुलाई फैसले से लोकसभा स्पीकर और उपराषटपति पर लिखकर इसका विरोध जताया है। सरकार ने अपने इस फैसले में संसद परिसर में जगह-जगह लगी मूर्तियों को परिसर में ही एक नए स्थान प्रेरणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धन का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ाते ही वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट

समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी गई है। एमएसपी वृद्धि की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट

कि धन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ाते ही सरकार के पास संसद स्थावर स्टैंक होने के बावजूद की गई है।

सामान्य ग्रेड धन के लिए एमएसपी 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति विंटर कर दिया गया है, जबकि एग्रेड किस्से के लिए इसे बढ़ाकर 2,320 रुपये प्रति विंटर कर दिया गया है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 2018 के केंद्रीय बजट में स्पष्ट नीतित निर्णय लिया था कि सरकार के पास संसद स्थावर स्टैंक होने के बावजूद की गई है। उन्होंने कहा कि लागत की गणना सीधेरोपी द्वारा वैज्ञानिक रूप से की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य नियम टन चावल का रिकॉर्ड भंडार है, जो 1 जुलाई के लिए आवश्यक खाद्य नियम टन चावल में लाभगत 53.4 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड भंडार है, जो 1 जुलाई के लिए आवश्यक खाद्य वर्ष के पास संसद स्थावर स्टैंक के लिए लाभगत की गयी थी।

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा बैठक में धन, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कापास सहित 14 खरीफ फैसलों के बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धन, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कापास सहित 14 खरीफ फैसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है। बता दें कि धन के न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है। बता दें कि धन के न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है।

हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों से पहले इसे अहम माना जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि आगामी खरीफ फैसले के लिए

## गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए

नीट परीक्षा को लेकर बोला सुप्रीम कोर्ट, काउंसिलिंग पर रोकतागाने से किया इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा को लेकर बोला सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिया। ये याचिका लोक स्टॉडेट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एजाम संटर्स पर गलत क्विरेजन पेपर बटन के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और पार्टी रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बैठक में धन, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कापास सहित 14 खरीफ फैसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी है। ये याचिका की गई थी कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी गई है।



याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी एजाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एजाम सेंटर के 67 कैंडीडेट्स को परे 720 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेश जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई ग्रेस को 5 मई को आयोजित नीट यूजी एजाम का परेर लीक होने की व्यापक याचिकायों को भी हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देने एनटीए का मनमाना फैसला है। स्टॉडेट को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। ये याचिका स्टॉडेट बेलफेयर के लिए काम करने वाले अव्युल्ला सोम्हमद फैज और डॉक्टर शेख रोशन ने दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इनमें एजाम में गड़बड़ी होने के इन्टर्नट्रूट के लिए ग







## संपादकीय

### बढ़ती गर्मी, घटता पानी

गर्मी के कारण हाल बेहाल है। सम्भवा उत्तर भारत तप रहा है। बुजुर्गों की स्मृति में भी नहीं है कि उन्होंने पहले कभी इतनी प्रचंड गर्मी की लगतार मार सी हो। दिल्ली और एनसीआर जैसे क्षेत्रों से लू के कारण मरने वालों की संख्या में लगतार बढ़ती हो रही है। और दूसरी तरफ जब देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हालाकार मचा हुआ है तो देश के जलाभाव वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। जो हो रहा है, वह अनायास या अचानक नहीं हो रहा है। दुनिया भर के पर्यावरणविद और जलवेता वर्षों से इस स्थिति की आशंका के प्रति चेतावनी जारी करते रहे हैं। भारत में भी बदलते तापमान और तदून्य समस्याओं को लेकर लगतार अपनी बातें समाने रखते रहे हैं।

पानी के संकट को लेकर और देश भर में भूजल स्तर की डरावनी गिरावट को लेकर भी चेतावनियां जारी होती रही हैं। इसका कारण खोजने के लिए अतिरिक्त अन्वेषण की जरूरत नहीं है। असंतुलित विकास की भेंट चढ़े देश के बन जंगल, निर्मलता से नष्ट किए गए स्थानिक जल स्रोत और जल संसाधनों पर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण यह स्थिति पेश हुई है। देश भर में गांव-देहातों तक जिन छोटी-छोटी नदियों का जाल बिछा हुआ था और जो पोखर तालाब जल के संरक्षण के मुख्य वाहक होते थे, वे अब कहीं दिखाई नहीं देते। मनुष्य के अनियन्त्रित लालच और हर स्तर पर व्यापक ब्रह्मांचार ने स्थितियों को कई गुना जटिल किया है तिस पर राजनीतिक दलों की बहार्याई समस्या की आग में घी डालती रहती है। सबसे ज्यादा मौजूदा उदाहरण इस समय दिल्ली का है। दिल्ली में दिल्लीवासियों की कथित सेवा को समर्पित आम आदामी पार्टी की सरकार है, और केंद्र में देश हित के लिए जीने-मरने का बाबा करने वाली भाजपा सरकार है और तमाशा यह है कि दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि दिल्ली के जल संकट के लिए एक दूसरे पर पूरी बेशर्मी से हल्ला बोल रहे हैं। जब दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर कर रहे हैं तुम समय दो जिम्मेदार पार्टियों और उनकी सरकारों के इस रवैये को शर्मनाक ही कहा जा सकता है। कहने में काई संकेत नहीं कि अगर वास्तविक समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी गणनीयिक दलों को रुख इतना गैर-जिम्मेदार है, तो देश और इसकी राजधानी को आने वाले भयानक संकटों से कोई नहीं बचा पाएगा।

## टीर्थ अदालत का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से 0.001 प्रतिशत लापवराही भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और एस्वीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ मंगलवार को पांच मई को हुई परीक्षा में छात्रों को कृपांक दिए जाने समेत अन्य शिकायतों से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ अब 8 जून ई को सुनवाई होगी। याचिकाओं में परीक्षा में अनियमितता बरते जाने की सीबीआई जांच और नीट-यूजी परीक्षा नये सिरे कराने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

अदालत ने एन्टीए और केंद्र सरकार से याचिकाओं पर दो दो हफ्ते के भीतर अपने जवाब दखिल करने को कहा है। लोक सभा चुनाव परिणाम आने की गहमगहमी के बीच ही नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए थे। अनेक परीक्षार्थियों को टॉपस छोड़ने और खासी संख्या में परीक्षार्थियों को कृपांक दिए जाने की जानकारी होने के बाद लगा कि दाल में कुछ गिरफ्तारियां हुई और पटना से लेकर गोधारा तक कई परीक्षा केंद्रों पर स्वापक स्तर पर अनियमितताएं बरते जाने की बातें सामने आने लगी। परीक्षा में धांधली के संकेत मिलने लगे और परीक्षार्थियों के परिजनों के साथ ही अनेक संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। कुछ परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर अधिभावक खासा खच्च करते हैं। अभ्यर्थी छात्र सामाजिक जीवन से कटकर मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में गत-दिन एक कर देते हैं। दरअसल, अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए इन्होंने बोर्डिंग को एन्टीए के लिए लिया है। जरूरी है कि सरकार सीटों बढ़ाने के लिए ढांचागत आधार को मजबूत करे। एन्टीए के वजूद में आने से पहले सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड पीएमटी की परीक्षा आयोजित करते थे जिसके आधार पर प्रवेश आसानी से मिल जाता था। लेकिन इस बीच अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने और एन्टीए जैसे निकाय के मेडिकल के अलावा अन्य तामापरीक्षाओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन्हें बोझ से एन्टीए का ढांचा कमज़ोर दिखाई पड़ने लगा है, उसके सामने मैनपावर की समस्या भी है। बहरहाल, जरूरी हो गया है कि छात्रों के साथ न्याय हो और इसके लिए एन्टीए-यूजी के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता।

## सामयिक : ये कैसा विरोध

वे माओवादी हिंसा को दरकिनार करके इसे गरीब आदिवासियों का विद्रोह कहती हैं। करीब ढेर दशक पहले उन्होंने रेड कॉरिडोर के केंद्र माने जाने वाले बस्तर की गुपचुप यात्रा की और दंडकारण्य में माओवादियों के साथ काफी वक्त बिताया। वे माओवादियों को भाई, साथी या कॉर्मेरेड कह कर लाल सलाम करने में फूस महसूस किया करती थीं। उन्हें संविधान और लोकतंत्र आदिवासियों की खिलाफ का अस्त्र नजर आता है। 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधती रॉय अपनी कीताब 'वॉकिंग विद द कॉर्मेरेड' में लिखती हैं - 'भारतीय संविधान, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, संसद द्वारा 1950 में लगू किया गया। यह जनजातियों और वनवासियों के लिए दुर्ख भरा दिन था। संविधान में उपनिवेशवादी नीति का अनुमोदन किया गया और राज्य को जनजातियों की आवास भूमि का संरक्षक बना दिया गया। मतदान के अधिकार के बदले में संविधान ने उनसे आजीविका और सम्मान के अधिकार छीन लिए।'

अरुंधती अपनी इस किताब में माओवादियों को आंतरिक सुरक्षा का खतरा बताते जाने का मखूल उड़ाती है। भारत की यह छात्र लेखिका मानवाधिकार के मुद्दों पर सरकार पर हमले करने से परहेज नहीं करती। अरुंधती कशीरी में तैनात फौज को जनता की दुश्मन बताती है। उन्हें संसद पर हमले के प्रमुख आरोपी अफजल गुरु से हमदर्दी रही। अपने ब्लॉग में वह भारत की पूरी न्याय प्रक्रिया पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं - 'लेकिन अब जब अफजल गुरु को फांसी दे गी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा संतुष्ट हो गई होगी। या फिर हमारे खुन का प्राप्त्यक्ष, लिखित या मौखिक क्रूप जिससे सामाजिक स्तर पर देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हो।'

संविधान का अवलोकन करें तो उनके दावों से उल्टा आदिवासियों को अंतरिक सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए अवधारी लेखिका की जाती है, लेकिन वे अक्सर भारत की अमांत्रित की छवि को निरुक्तशाता के करीब ले आती हैं। अरुंधती गरीब आदिवासियों के तहत मुकदमा चलेगा। अरुंधती अच्छी लेखिका है, और उन्हें प्रसंद करने वाले देश-विदेश के कई लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अरुंधती पर हिंसा के लिए भारतीय संविधान को शोषण के अखंत के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है।

भारत की विविधता और जटिलता के लिए जातियों को आंतरिक सुरक्षा का खतरा बताते जाने का मखूल उड़ाती है। उन पर भारत विवेधी भाषण देने और कशीरी अलगावाद का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। अरुंधती भारतीय लेखिका के रूप में देश-विदेश में आंतरिक विविधतायों के खिलाफ का अस्त्र नहीं है। अब हमले करने से परहेज नहीं करती। अरुंधती कशीरी में तैनात फौज को जनता की दुश्मन बताती है। उन्होंने देश-विदेश के कई लोगों के लिए भारतीय संविधान को शोषण के अखंत के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है।

संविधान का अवलोकन करें तो उनके दावों से उल्टा आदिवासियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46, राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और अधिकार देने के लिए उन्हें एक उपर्युक्त विविधतायों के अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है।

भारत की विविधता और जटिलता के लिए जातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46, राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और अधिकार देने के लिए उन्हें एक उपर्युक्त विविधतायों के अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है।



में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आंतरिक प्रावधान किया गया है। संविधान की पाचवी अनुसूचित की अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातियों आवादी के विवरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत का रेड कॉरिडोर का क्षेत्र सशस्त्र विद्रोह के लिए जाना जाता है, और यह इलाका हिंसाग्रस्त रहा है। अरुंधती आदिवासियों के हितों के लिए सुखर रहे, यह उनका अधिकार है लेकिन संवैधानिक तंत्र को शोषित वर्ग के खिलाफ प्रचारित करने की उनकी कोशिशें भारत की आंतरिक शांति को धंग करती दिखाई पड़ती है। भारत का संविधान अभियान के लिए जाने



भारत विध के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में से एक है और इसकी संपत्ति के सबसे बड़े स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है- भूमि की पैदावार। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 29.4 प्रतिशत है। इससे कठीब 64 प्रतिशत सेवा क्षेत्र जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा सुनियित करने की दिशा में वर्ष दर वर्ष कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।

कृषि विज्ञान आधारित उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्र है तथा इसमें रोजगार संभावनाएं हैं। पशु और पादप शोधकर्ता, खाद्य वैज्ञानिक, वस्तु ब्रॉकर, पोषणविद, कृषि प्रकारा, बैंकर्स, बाजार विश्लेषक, बिक्री व्यापारियक, खाद्य संसाधक, पन्न प्रबंधक, कच्चीवाल विशेषज्ञ आदि के रूप में कृषि क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा कृषि शिक्षा और पशु विकास विभाग महाविद्यालयों द्वारा संचालित की जाती है। कृषि विज्ञान के प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान भाग हैं, जिन्हें कृषि के व्यवहार तथा इसे सम्बद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में उत्पादन तकनीकें जैसे सिंचार्च प्रबंधन, अनुरासित नाइट्रोजेन इन्फूट्स गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कृषि उत्पादन में सुधार, प्राथमिक उत्पादों का अतिम- उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तन, विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों की रोकथाम तथा सुधार जैसे मिट्टी निम्नीकरण, कवरा प्रबंधन, जैव-पुनःउत्पाद रैखिक उत्पादन परिस्थितिकी, फसल उत्पादन मॉडलिंग से संबंधित परपारगत कृषि प्रणालियां, कई बार इसे जैविका कृषि भी कहा जाता है, जो विश्व के सर्वाधिक गरीब लोगों का भरण-पोषण करती है। ये परपारगत पद्धतियां कांगों रुचिकर हैं वैयोंकि कई बार ये औद्योगिक कृषि की बजाय ज्यादा प्राकृतिक रिस्थितिकी व्यवस्था के साथ समाकलन का स्तर कायम रखती हैं जो कि कुछ आधुनिक कृषि प्रणालियों की अपेक्षा ज्यादा दीर्घकालिक होती हैं।

## न घबराएं ग्रुप इंटरव्यू से



जीके या जनरल अवेयरनेस के बिना आप कोई भी कॉम्पिटीटिव एजाम पास करने की सोच भी नहीं सकते। बैंकिंग एजाम्स के लिए भी यही बात लाग जाती है। जनरल अवेयरनेस के तहत इकॉनॉमी, नियोगाधी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स आदि सब्जेक्ट्स काफी अहमियत रखते हैं और एजाम्स में इनसे ही संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल लेबल के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। दायरा बड़ा या यूं कहाँ कि अनलिमिटेड होने के कारण इस सब्जेक्ट की तैयारी करना हर किसी के लिए बड़ी चुनौती होती है। सवालों को लेकर क्या सब्जेक्ट भी नहीं लगा जा सकते हैं। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बैंक एजाम्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट का फोकस उन टॉपिक्स पर ज्यादा होता है, जिनका बैंकिंग और इकॉनॉमी से वास्ता होता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों का इनसे ही वास्ता पड़ता है और एजाम में यही देखा जाता है कि इनमें स्टडेट्स की किंतुनी समझ है? वैसे तो इस सब्जेक्ट की तैयारी के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि उसने सब कर लिया है, लेकिन अपने आप को देश-दुनिया की घटनाओं से अपडेट रख अपने लिए जमीन जरूर तैयार कर सकते हैं।

आपकी सफलता बहुत हद तक जनरल अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। इसकी कई वजहें हैं। अबल तो यह कि हर एजाम में इसके अंक काफी होते हैं। दूसरा यह कि जनरल अवेयरनेस के सवालों को हल करने में बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए आप इस सेक्टर में समय बचा कर अन्य सेक्षन में लगा सकते हैं। एजाम में भी इस सेक्षन को पहले करने की जरूरत होती है। जो लोग पहले दूसरे सेक्षन की शिक्यत करते हैं। अच्छा सेक्षन में अच्छा होने और अच्छा करने के बावजूद बहुतों के लिए एजाम में फेल होने का यह भी एक कॉमन रीजन है।

### इकॉनॉमी और फाइनेंस

बैंकों के एजाम के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस इकॉनॉमी और फाइनेंस पर ही रखें। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्ल बैंक और एकीवी से लेकर रिजर्व बैंक तक के बारे में। नामी कंपनियों और उनके प्रदर्शन से भी खुद को वाकिफ रखें। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले टर्म और शब्द संक्षेप पर भी पकड़ बनाएं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और खेल की भी अच्छी तैयारी रखनी चाहिए।

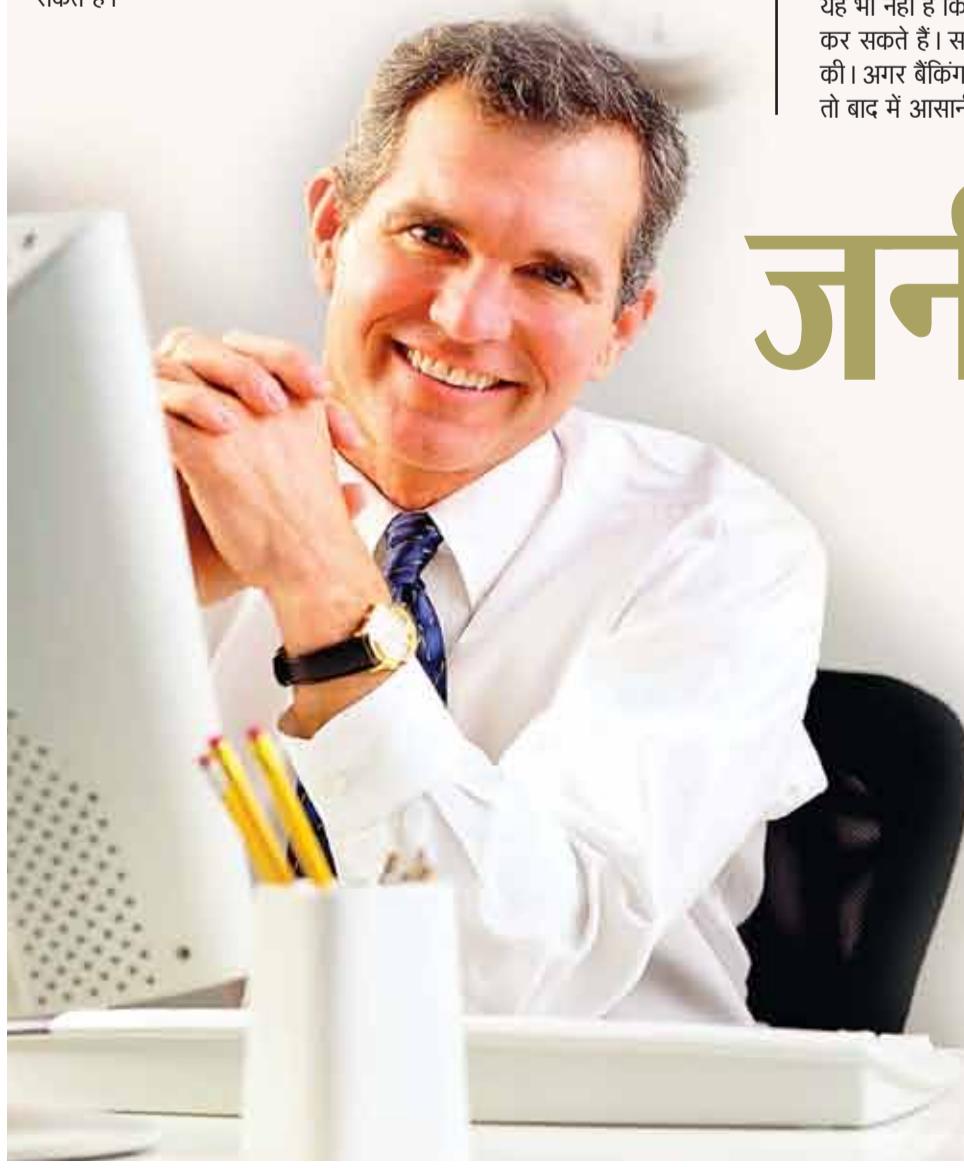
### रेग्युलर बैंकें

जनरल अवेयरनेस की तैयारी को काफी लोग हल्के में लेते हैं। लोग मान लेते हैं कि बैंक के लिए रीजिनिंग और मैथ्स अहम है, जनरल अवेयरनेस नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है और यह भी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी थोड़े दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरत है चीजों को समझने की। अगर बैंकिंग और फाइनेंस के टर्म्स आप समझ जाएंगे तो बाद में आसानी से खुद को अपडेट रख सकते हैं। किसी

अन्य चीज की तरह इस सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए भी नियमिता की जरूरी है। करंट अफेर्स से खुद को अपडेट रखने का रुटीन बनाएं इसलिए तैयारी अडवांस में ही शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा करते खुद और दूसरों में अंतर देख सकते हैं। खुद को अपडेट रखने के लिए सबसे पहले तो न्यूज पेपर्स का सहारा लें। इसके अलावा करंट अफेर की एक दो अच्छी पत्रिका भी नियमित रूप से पढ़ें। जनरल अवेयरनेस के सवालों का जायजा आप पिछले एजाम्स के सवालों से से ले सकते हैं। एक और बात भी ठीक तरह समझ लें कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए आप किसी एक बुक के सहारे नहीं रख सकते हैं। बाजार में हर जरूरत के हिसाब से काफी पुस्तकें और फार्मजीस आ रही हैं। आप उनमें से कुछेक के नियमित पाठक बन सकते हैं। इस क्रम में समाचार चैनलों और इंटरनेट का भी सहारा लिया जा सकता है। नेट पर भी अब हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी काफी कुछ उपलब्ध है।



## जर्नलिज्म, बेस्ट कैरियर



इन दिनों ज्यादातर युवाओं के लिए मीडिया आकर्षक कैरियर बनता जा रहा है। यदि लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं और आपकी काम्युनिकेशन एकल बढ़िया है, तो मीडिया आपके लिए बेस्ट कैरियर साबित हो सकता है। दरअसल, आज मीडिया का काफी विस्तार हो चुका है। जे केवल अखबार, टीवी और ईडियो, बल्कि इंटरनेट, नैटवर्क, फिल्म भी इसके विस्तारित खेत्र हैं। कैरेट इंवेट्स, ट्रेड्स एवं संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्टर करना, एनालाइज करना आदि जर्नलिज्म के मुख्य काम हैं।

ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स एंट्रेस एजाम आयोजित करते हैं। इसमें रिटेन टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्केशन भी होता है। लिखित परीक्षा में स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स, जे नेशनल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड की जाती है। एम्सीआरसी के अफिशियलिंग डायरेक्टर ऑबेद सेंट्रीकी के अनुसार, एंट्रेस एजाम के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। टेस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इन्स्यू संबंधित ज्ञान को परखा जाता है। करेट अफेर्स की जानकारी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के प्रोफेसर सप्त कुमार कहते हैं कि जर्नलिज्म के लिए जरूरी तत्व है - करेट न्यूज पर आपकी पकड़। ऐसे कैरियर ही अच्छे जर्नलिज्म बनते हैं, जिन्हें न्यूज की अच्छी समझ होती है और जिनकी राइटिंग बढ़िया होती है। साथ ही, उनका अपने पेशे के प्रति कमिटमेंट होना भी जरूरी है। दरअसल, किसी भी खबर का विश्लेषण कर उसे सरल रूप में पेश करना ही।

मास कार्यनिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि आप इस पेशे में सफल होना चाहते हैं, तो न्यूज पेपर्स, मैग्जीन्स और करेट अफेर्स संबंधित बुक्स जरूर पढ़ें। इंटरव्यू है असली परीक्षा: दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में बैचलर करने के बाद मैं पीजी करना चाहता था। मैं प्रतिदिन एंट्रेस एजाम की तैयारी के लिए दो लीडिंग न्यूजपेपर्स और कई मैग्जीन्स पढ़ा करता था। एंट्रेस एजाम राइटिंग स्किल और सामयिक घटनाओं के प्रति आपकी जागरूकता की जांच के लिए किए जाते हैं। इसमें सफल होना आसान है। असली परीक्षा इंटरव्यू के दोरान आपके न्यूज सेस, काम्युनिकेशन स्किल और पेशेंस की भी जांच-परख होती है। यदि आप दब्बा किस्म के इंसान हैं या जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, तो आपको इस पेशे के लिए लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नजरिया बनाना होगा कि आपका रखभाव इस पेशे के अनुकूल है या नहीं।



